1	2	3	4
पूर्वी क्षेत्र			
9. कलकत्ता	84–90	95–102	13 प्रतिशत
10. पटना	85–94	100–104	11 प्रतिशत
11. भुवनेश्वर	82–86	84–87	1 प्रतिशत
12. गौहाटी	95–100	112–115	15 प्रतिशत
पश्चिमी क्षेत्र			
13. बम्बई	89–93	95–100	8 प्रतिशत
14. भोपाल	75–78	86–88	13 प्रतिशत
15. गोवा	70–84	88–95	13 प्रतिशत
16. अहमदाबाद	70–82	90–98	20 प्रतिशत
17. राजकोट	78–82	90–98	20 प्रतिशत
18 बड़ोदा	78–82	92–98	20 प्रतिशत
19. सूरत	78–82	98–99	21 प्रतिशत
दक्षिणी क्षेत्र			
20. मद्रास	82–85	87–92	8 प्रतिशत
21 त्रिवेन्द्रम	88–93	100–103	11 प्रतिशत
22. बंगलौर	82–87	87–94	8 प्रतिशत
23. हैदराबाद	72–74	78–82	11 प्रतिशत
24. कालीकट	86–94	98–102	9 प्रतिशत

Maharashtra Chief Minister's letter to Prime Minister on formation of Development Boards under Article 371(2)

1527. SHRI NARESH C. PUGLIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Chief Minister of Maharashtra has sent a letter to the Prime Minister on 4th December, 1990 about formation of Development Boards under Article 371(2) of the Constitution; if so, what are the details thereof;

(b) whether the Chief Minister of Maharashtra has also desired such Boards for the Western Maharashtra and Bombay; if so, what is Government's reaction thereto;

(c) whether formation of Boards for the backward regions like Vidarbha, Marathwada and Konkan only is under Government's consideration; and

(d) if so, what are the details in this regard and by when the same are likely to be formed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) Yes, Sir. The letter concerns early setting up of Development Boards in Maharashtra.

(b) The Chief Minister's proposal relates to the setting up of Development Boards for Vidarbha, Marathwada, Konkan and the rest of Maharashtra.

(c) and (d) The earlier proposal of the Government of Maharashtra was for issuing President's Order in terms of article 371(2) of the Constitution to facilitate establishment of separate Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra. The revised proposal suggests inclusion of Konkan also in article 371(2) and for making a

change in the provision relating to "the special responsibility" of the Governor. The proposals have been examined in the Ministry. It does not seem possible to specify any time limit as the proposals also involve Constitutional amendments.

बांग्ला देश से अवैध प्रवेश को रोकने के लिए अनुदेश

1528. **श्री बलराम सिंह यादव :**

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बांगला देश से भारत में अवैध प्रवेश को रोकने के लिए हाल ही में कोई अनुदेश जारी किए हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सीमा से अवैध प्रवेश रोकने के लिए हाल ही में असम सरकार ने अतिरिक्त प्रबन्ध किए जाने हेतु प्रस्ताव भेजे थे ;

(ग) यदि हां, तो उन प्रस्तावों की रूपरेखा क्या है और उन्हें कार्यान्वित करने में क्या कठिनाइयां थीं ; और

(घ) क्या देश की पूर्वोत्तर सीमा पर बाड़ लगाने के काम को पूरा कर लिया गया है; यदि नहीं, तो इस कार्य के कब तक पूरा किये जाने का लक्ष्य है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) राज्य में अवैध रूप से होने वाले प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए बड़ी संख्या में पदों को सृजित करने से संबंधित प्रस्ताव असम सरकार से प्राप्त हुआ था । इन प्रस्तावों को व्यवहारिक नहीं पाया गया ।

(घ) असम में (158 कि०मी०) और मिजोरम में (231 कि०मी०) के क्षेत्र में बाड़ लगाने का काम चल रहा है। आशा की जाती है कि मार्च, 1996 तक परियोजना के एक बड़े भाग का काम पूरा हो जाएगा ।

देश में कागज का उत्पादन करने वाले रूग्ण एकक

1529. **श्री बलराम सिंह यादव :**

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक अनुमान के अनुसार देश में लगभग 270 कागज उत्पादक एककों में से 115 एकक रुग्णावस्था में हैं या भारी घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इंडियन पल्प एण्ड पेपर टेकनीकल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कागज उत्पादक उद्योग के आधुनिक बनाने तथा पुनर्गठित करने की आवश्यकता के संबंध में कुछ सुझाव दिये हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) प्राप्त सूचना के अनुसार, कुल 311 एककों में से 77 पेपर एकक उत्पादन संबंधी सूचना नहीं भेज रहे हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) सरकार कागज उद्योग की समस्याओं पर कड़ी निगरानी रखती है। कागज उद्योग के निरंतर विकास तथा आधुनिकीकरण के लिए नीतिगत उपाय करना एक अनवरत प्रक्रिया है ।

निगेटिव इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ

1530. **श्री बलराम सिंह यादव :**

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 दिसम्बर, 1990 के इंडियन एक्सप्रेस